REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
High Court
उच्च न्यायालय
Part -2
LIVE
06-02-2025 07:00 PM

संयुक्त उच्च न्यायालय

1. J&K उच्च न्यायालय → J&K व लद्दाख
2. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय → पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़
3. मुम्बई उच्च न्यायालय → महाराष्ट्र, गोवा, दमनद्वीव एव दादर हवेली
4. केरल उच्च न्यायालय → केरल व लक्षद्वीप
5. चैन्नई उच्च न्यायालय → तमिलनाडु, पुडुचेरी
6. कोलकाता उच्च न्यायालय → प. बंगाल, अण्डमान एव निकोबार
7. गोवाहाटी उच्च न्यायालय → असम, नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय

भारत का सबसे नविनतम उच्च न्यायालय → अमरावती [आंध्रप्रदेश]

↓

1 Jan. 2019

अधीनस्थ न्यायालय

अनु. 233 → जिला न्यायाधीश

- → नियुक्ति
- → पदस्थापन
- → पदोन्नति

} राज्यपाल

योग्यता → न्यूनतम 7 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।

→ HC द्वारा सिफारिश कि हो।

अधिनस्थ न्यायालयो पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का रहेगा।

स्थानीय स्वशासन

- ग्रामिण स्थानीय स्वशासन
  - ↓ पंचायतीराज
- शहरी स्थानीय स्वशासन
  - ↓ नगरीय स्वशासन

पंचायती राज

महात्मा गांधी "भारत की आत्मा गांवो मे निवास करती है यदि गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा और गांव नष्ट को भारत नष्ट"

अनु. 40 → पंचायतो का गठन

1951 → पंचायतीराज के लिए एक मंत्री का गठन →

1952 → सामुदायिक विकास कार्यक्रम → (USA के सहयोग) →

1953 → राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम → [ford foundation के सहयोग से] →

असफल

* असफलता का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया

बलवंत राय मेहता समिति

- गठन – 1957
- रिपोर्ट → 1957

कारण

- जनभागीदारिता की कमी
- नौकरशाही का प्रभाव
- वित्त की कमी

सिफारिश

- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
- त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था

ग्राम स्तर → ग्राम पंचायत

मध्यम स्तर → पंचायत समिति

जिला स्तर → जिला पंचायत / जिला परिषद

2 oct. 1959 को राजस्थान के नागौर जिले की बगदरी पंचायत से भारत में पंचायतीराज व्यवस्था की शुरुआत की

- → उद्घाटन ⟶ जवाहर लाल नेहरू
- → राष्ट्रपति ⟶ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- → मुख्यमंत्री → मोहन लाल सुखाड़िया
- → राज्यपाल → सरदार गुरुमुख निहाल सिंह
- → पंचवर्षीय योजना → दूसरी पंचवर्षीय योजना

पंचायतीराज → लागु → राजस्थान
→ आंध्रप्रदेश

पंचायतीराज के चुनाव → आंध्रप्रदेश
→ राजस्थान
} – 1960

→ लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जनक → बलवंत राय मेहता